ग्रामीण भारत की मज़बूत होती बुनियाद

–देविका चावला

केंद्र सरकार 'नए भारत' के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और ग्रामीण भारत के दीर्घकालिक विकास हेतु ठोस नतीजे हासिल करने के लिए काम कर रही है। लंबे अर्से तक हमारे देश के गांव सिर्फ 'दर्शक' की भूमिका में रहे और आर्थिक बदलाव का लाभ पाने में शहरों के मुकाबले पीछे छूटते रहे। अतः अब समय आ गया है कि विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण भारत भी न केवल सक्रिय भागीदार की भूमिका में नज़र आएं बल्कि आने वाले वर्षों में भारत के उत्थान के दारोमदार बनें।

ज़्यादातर लोग इस बात को समझते हैं कि देश के गांव हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हालांकि, इस बारे में जागरूकता कम है कि गांवों के विकास से ही, आने वाले वर्षों में विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी इस अर्थव्यवस्था को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इस लेख में ऐसे ही तमाम पहलुओं पर बात की गई है। लेख में पिछले सात वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सतत और समावेशी ग्रामीण विकास की दिशा में किए गए कार्यों का भी विश्लेषण किया गया है। साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। साथ ही, कृषि–आधारित क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए कई स्तरों पर काम करने की रणनीति अपनाई गई है जो सभी के लिए समृद्धि, विकास आदि पर केंद्रित हो।

दरअसल, इन रणनीतियों के जरिए ग्रामीण आबादी को प्राकृतिक गैस, पीने के पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का काम लगातार जारी रखना है, ताकि समाज के सबसे अहम तबके को ज़रूरी सुविधाओं का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री के 'स्वच्छ भारत मिशन' में भी यह बात नज़र आती है, जिसे 2014 में शुरू किया गया था। यह मोदी सरकार की सबसे पहली गांवों पर केंद्रित देशव्यापी योजना थी। योजना के शुरू होने के सात साल बाद इसके उल्लेखनीय नतीजे देखने को मिले हैं।

साल 2014 में देशभर में 38 प्रतिशत घरों में शौचालय की सुविधा थी और अब यह आंकड़ा 100 प्रतिशत तक पहुंच गया है। देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े हिस्से में तकरीबन 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है। इस तरह, तकरीबन 6,00,000 गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जिससे देश की बड़ी आबादी को बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता का लाभ मिल सका है।

इसके अलावा, पांच साल पहले शुरू की गई योजना 'उज्ज्वला योजना' का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य के साथ–साथ ऊर्जा की सुरक्षा और बेहतर जीवन–स्तर प्रदान करना है। इस योजना के तहत 2016 से अब तक तकरीबन रसोई गैस के 8 करोड़ सिलेंडर का वितरण किया जा चुका है।

जीवन की मौलिक आवश्यकताओं में घर भी शामिल हैं। गांवों में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं हैं या फिर कच्चा मकान है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की शुरुआत की, ताकि समाज के सबसे गरीब तबके को भी पक्का मकान उपलब्ध हो सके। इस योजना के तहत, अब तक कुल 1.5 करोड़ घरों का निर्माण हो चुका है, जिससे लोगों की गरीबी दूर करने में भी मदद मिली है।

ग्रामीण आबादी का जीवन बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अहम योजना 'आयुष्मान भारत योजना' की शुरुआत की है। 'आयुष्मान भारत योजना' दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इससे 2 करोड़ ऐसे लोगों को लाभ मिला है, जिनकी आय बेहद कम है और पैसे की कमी की वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा के व्यापक दायरे के जरिए ग्रामीण लोगों के लिए एक न्यूनतम जीवन–स्तर सुनिश्चित करने के अलावा ग्रामीण भारत की आर्थिक बुनियाद मज़बूत करना भी जरूरी है, ताकि सभी के लिए बेहतर जीवन–स्तर उपलब्ध हो सके। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर और विविधतापूर्ण बनाने की दिशा में सरकार ने काफी प्रयास किया है, ताकि देश के बड़े आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने में सहूलियत हो सके।

इसके तहत, केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण अभियान चलाया, ताकि हर गांव में बिजली पहुंच सके। इसके बाद 'उजाला योजना' पेश की गई, जिसके तहत 36 करोड़ से भी ज़्यादा एलईडी बल्ब का वितरण किया गया। इस तरह, लंबे समय से अंधेरे में रहने को मजबूर गांवों तक बिजली की रोशनी पहुंचाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सड़कें बनाकर सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण काम किया है। पिछले सात सालों में 2.25 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। इन सड़कों के जरिए देश के 97 प्रतिशत गांवों को बाकी हिस्से से जोड़ा गया है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों का अहम योगदान होता है, लिहाज़ा किसानों की आय में बढ़ोत्तरी, मिट्टी की बेहतर सेहत का ध्यान रखना और ग्रामीण इलाके के कृषि क्षेत्रों में विविधता की गुंजाइश बनाना आदि बेहद जरूरी हैं। ये तमाम गतिविधियां न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में उच्च आर्थिक विकास के लिए जरूरी हैं, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा के मामले में वैश्विक–स्तर पर भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भी इनकी भूमिका अहम है। जन–धन–आधार–मोबाइल (जेएएम), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई–राष्ट्रीय कृषि बाज़ार, प्रधानमंत्री–किसान सम्मान निधि योजना (पीएम–किसान), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे कार्यक्रमों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी गतिविधि को पूरी तरह से बदलने में मदद मिली है। कार्यक्रमों में डिजिटल मीडिया की भूमिका को भी कम करके नहीं आंका जा सकता है। जेएएम और डीबीटी की वजह से सरकारी फंडों की बर्बादी रोकने में मदद मिली है। इससे सरकारी खजाने को अरबों डॉलर की बचत हुई और इस रकम का बेहतर आवंटन सुनिश्चित हो पाया। इसके अलावा, भारतनेट कार्यक्रम के जरिए ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा के आधार पर देश की 1.6 लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल तरीके से जोड़ा गया है। इस तरह, हाल के वर्षों में ग्रामीण इलाकों में खपत और मांग को भी बढ़ावा मिला है। भारत में मोबाइल डेटा और कॉल की दरें काफी सस्ती होने के कारण आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ी है। सरकार की सेवा प्रदाता इकाई कॉमन सर्विस सेंटर (आम सेवा केंद्र) के बढ़ते नेटवर्क के चलते भी ग्रामीण इलाकों में स्थिति बेहतर हुई है। लंबे समय तक हमारे गांव पूरी तरह कृषि पर आधारित रहे। हालांकि, हाल के दशकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि कृषि के ज़रूरत से ज़्यादा बोझ को थोड़ा कम किया जा सके और कृषि से अलग गतिविधियों मसलन उद्यमिता, माइक्रो फाइनेंस, हथकरघा, स्थानीय उद्योग–धंधों के विकल्पों को बढ़ावा दिया जा सके।

सरकार ने मुद्रा योजना, वन धन योजना, एक ज़िला–एक उत्पाद, स्किल इंडिया (कौशल भारत), कौशल विकास योजना और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए ग्रामीण–स्तर पर उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत लक्ष्यों का सम्मिलन किया है। ज़्यादा उत्पादन क्षमता, युवा आबादी और कुशल मानव संसाधन जैसी खूबियों की वजह से ग्रामीण आर्थिक गतिवधि के लिए जबर्दस्त संभावनाएं हैं और इसका लाभ उठाया जाना अभी बाकी है।

इन तमाम कदमों के आधार पर कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार 'नए भारत' के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और ग्रामीण भारत के दीर्घकालिक विकास हेतु ठोस नतीजे हासिल करने के लिए काम कर रही है। लंबे अर्से तक हमारे देश के गांव सिर्फ 'दर्शक' की भूमिका में रहे और आर्थिक बदलाव का लाभ पाने में शहरों के मुकाबले पीछे छूटते रहे। सरकार ने बार–बार यह दिखाया है कि गांवों के विकास के बिना भारत में कोई आर्थिक या सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती। अतः अब समय आ गया है कि विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण भारत भी न केवल सक्रिय भागीदार की भूमिका में नज़र आएं बल्कि आने वाले वर्षों में भारत के उत्थान के दारोमदार बनें। ग्रामीण भारत के लिए शायद इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।

(लेखिका इनवेस्ट इंडिया की रणनीतिक निवेश शोध इकाई में शोधकर्ता हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)